Ministry of Coal is being insisted for more coal to be supplied. For long, efforts are being made to improve the coal supply and we request the Ministry of Coal also for this. The question raised by the hon. Member pertains to the Coal Ministry. So, I think the Coal Ministry could answer better.

Training Programmes by TRIFED

*325. SHRI NAND KUMAR SAI: Will the Minister of TIRBAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED) has been organizing training programmes for ST artisans and minor forest produce gatherers for improving the production and sale of their various products;

(b) if so, the details in this regard;

(c) the details of technical training centres set up by TRIFED in various tribal areas in the country; and

(d) the number of ST artisans who have benefited in each of such technical training centres during 2008-09 and 2009-10?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRIBAL ARRAIRS (SHRI TUSHARBHAI CHAUDHARY): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. The Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED) has been organizing training programmes for Scheduled Tribe (ST) (i) artisans and (ii) Minor Forest Produce (MFP) gatherers for improving the production and sale of their various products. The training imparted by TRIFED relates to Handicrafts, Honey gathering, Gum Karaya collection, Mahua Flower collection, Lac cultivation, and making of leaf cups and plates (Dona/Pattal).

1. **Training for tribal artisans**:

TRIFED conducted Handicraft Development Training for tribals in 3 modules.

(i) Primary Level Training (PLT)

(ii) PLT-cum-Design Workshop Training followed by Reinforcement Training (PLT-DWT-RT)

(iii) Design Workshop Training (DWT)

(i) Primary Level Training (PLT)

This is meant for potential tribal members, where training on basic techniques of craft is being imparted to equip the artisans for producing the crafts. So far TRIFED has organized 37 PLT training and benefited 760 tribal artisans.

(ii) PLT-cum-Design Workshop Training followed by Reinforcement Training (PLT-DWT-RT)

This training is for those tribal members, who perform well in the PLT and show potential of becoming craftsperson of better quality. The outcome of this intervention is to produce the artifacts, which are aesthetically acceptable, technically suitable and commercially viable. 243 tribals artisans have received this training in the 12 PLT DWT_RTS organized till date.

(iii) Design Workshop Training (DWT)

This training is for the existing artisans/suppliers of TRIFED. It is related to further design and technology upgradation based on market feedback on the needs of product innovation, feature addition, uses diversification, etc. on utility and decorative products. 120 tribal artisans have benefited from the 6 DWTS undertaken so far.

II. Training for MFP Gatherers:

(1) **Honey collection:**

The basic objective of the Project is to improve the skill of tribal Honey Gatherers for harvesting of Honey in a scientific and eco friendly manner so that they are able to get better quality and quantity of Honey and ultimately better income. So far, TRIFED has organized training for 12,147 tribal beneficiaries in the various States.

(2) **Gum Karaya:**

The training is aimed at improving the skill of Gum Pickers in scientific tapping, collection, grading, packing and marketing of Gum Karaya. So far TRIFED has imparted training to 15,300 tribal gum pickers.

(3) **Mahuwa Flower:**

Under the Project, TRIFED provides training to the Mahuwa Flower collectors on the best practices of Mahuwa Flower collection, drying/ primary processing, grading, packing, value addition, storage, marketing etc. So far TRIFED has imparted training to 1,000 beneficiaries in the State of Madhya Pradesh.

(4) **Lac Cultivation:**

The basic objective of the training is to improve the income of the Lac growers by promoting Lac cultivation activities during the lean period of agriculture. So far, TRIFED has undertaken mobilization and orientation programme for 4,790 beneficiaries, On-Farm training for 1,700 beneficiaries and training of trainers programme for 427 tribals, in the States of Jharkhand, Madhya Pradesh, Orissa and West Bengal.

(5) **Leaf Cups & Plates (Dona & Pattal):**

The training aims at developing the skill among the tribals to produce leaf cups and plates by using moulding and stitching machines. So far, 1240 beneficiaries have been given training and provided Dona/Pattal stitching machines.

(c) and (d) TRIFED has not set up any technical training centre in the country for the purpose of training tribal artisans and Minor Forest Produce gatherers.

श्री नन्द कुमार साय : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मधु संग्रह, गम कराया, मछुआ के फूल आदि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रशिक्षण केन्द्रों में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है और यह खर्च किस-किस प्रकार से किया गया है, इसका पूरा ब्यौरा दें?

श्री तुषारभाई चौधरी : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं उसमें हम लोगों ने करीबन हनी कलेक्शन के लिए 12,147 और गम पिकर्स के लिए 15,300 और दौना पत्तल के लिए 1,240 हैं। इन सबको मिलाकर इसमें सब श्रेणियों में 6 लाख 36 हजार रुपए हमने छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग देने के लिए खर्च किया है।

श्री नन्द कुमार साय : मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने जो प्रशिक्षण केन्द्र छत्तीसगढ़ में स्थापित किए और इसमें 6 लाख 36 हजार खर्च किए हैं, इसमें से जो लाभांवित हुए उनको कितनी राशि का लाभ मिला है और किस प्रकार का लाभ मिला है, यह जानकारी आप देने का कष्ट करें। माननीय सभापति, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपने उत्तर दिया है कि तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई है। तो क्या भविष्य में तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के संबंध में सरकार के पास कोई योजना है? छत्तीसगढ़ में लाभान्वितों की राशि का किस प्रकार से...।

श्री सभापति : आपका सवाल हो गया है।

श्री तुषारभाई चौधरी : सर, जहां तक तकनीकी शिक्षण के लिए इंस्टीटयूट की स्थापना का सवाल है, यह सब minor forest produce gathers जो होते हैं, वे बहुत scattered रहते हैं। उनको एक जगह पर लाकर ट्रेनिंग देना, यह बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए हम तीन तरह की ट्रेनिंग देते हैं। हम इसके लिए मास्टर ट्रेनर तैयार कर रहे हैं, जो गांव में जाकर minor forest produce gathers को ट्रेनिंग देंगे और वे लोग वहीं पर ट्रेनिंग लेकर के इम्प्रूवमेंट कर सकें, क्वालिटी इम्प्रूव कर सकें, क्वांटिटी इम्प्रूव कर सके और इको-फ्रेंडली मैनर में अच्छी तरह से काम कर सकें। इस प्रकार से हमारा मंत्रालय उनके लिए काम कर रहा है।

श्री नन्द कुमार साय : सभापति महोदय...।

श्री सभापति : आपके सवाल अब खत्म हो गए।

सुश्री सुशीला तिरिया : धन्यवाद सर। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि किसी भी राज्य के ट्रायबल एरिया में नेशनल लेवल का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ऐसा मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि गांव-गांव में जो ट्रेनिंग देने की बात उन्होंने जवाब में कही है, इस तरह की ट्रेनिंग अब तक राज्यो में और जिलों में कितनी हो चुकी है और ट्रेनिंग लेने के बाद इसका क्या नतीजा निकला है? ट्रेनिंग देने के बाद लघु उद्योग बनाने की कोई ट्रायबल इंटरप्रेनियोर करना चाहता है, तो जहां पर लघु वन उद्योग का प्रोडक्शन ज्यादा है अगर वह कुछ करना चाहेगा, तो उसको मदद देने के लिए क्या कोई प्रोग्राम बनाया है?

श्री तुषारभाई चौधरी : चेयरमैन सर, मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हनी गैदरर्स हैं, उसके लिए हमने पूरे देश में 12147 लोगों को ट्रेनिंग दी है, जो गम पिकर्स हैं, उसके लिए हमने 15300 लोगों को ट्रेनिंग दी है, जो महुआ फलावर्स गैदरर्स हैं, उसमें हमने 1000 लोगों को ट्रेनिंग दी है और जो Lac growers हैं, उसमें हमने करीबन 7000 लोगों को ट्रेनिंग दी है और Dona and Pattal की की हमने 12040 लोगों को ट्रेनिंग दी है।

जहां तक tribal artisans का सवाल है artisan के लिए हम तीन प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं। पहला हमारा काम प्राइमरी लेवल ट्रेनिंग देना, उसमें 60 दिन की सीमा होती है, उसमें हम ऐसे लोगों को पसन्द करते हैं, जो artisan के साथ जुड़े हुए हों, उनके बेटे, उनके सगे-संबंधियों को हम ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वह कला लुप्त न हो जाए। दूसरी, हम उनको 45 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद Design Workshop Training होती है, वह 15 दिन की होती है और तब तक वह आर्टिस्ट पूरा तैयार हो जाता है। इस प्रकार से हमारी कार्यवाही चल रही है और हर एक ट्रेनिंग में 20 लाभार्थी होते हैं, तो उनके उनके ऊपर हम एक लाख रुपया खर्च करते हैं। स्टेटवाइज जितने भी लाभार्थी होंगे, प्रति 20 के हिसाब से हम एक लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराते हैं।

श्रीमती वृंदा कारत : सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि आपने उन लोगों को ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद क्या आपने कोई समीक्षा की है, कोई रिव्यु किया है जिन ट्रायबल्स ने ट्रेनिंग ली, उसके बाद उनको कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? यह मैं इसीलिए पूछ रही हँू, क्योंकि हकीकत यह है कि इस समय पूरे ट्रायबल इलाके में minor forest produce का इतना संकट है और दाम इतने गिर चुके हैं कि चाहें आपने ट्रेनिंग दी या चाहें आपने कुछ भी किया, लेकिन उनको जो दाम minor forest produce के मिल रहे हैं, वे बहुत कम मिल रहे हैं। आपने हनी की बात की है, यहां बाजार में हनी का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ट्रायबल्स जो इतना कष्ट करके हनी गैदर करते हैं, हनी गैदरर्स स्पाट पर उसका दाम कम से कम एक तिहाई गिरा है। अभी मैं एक प्रदेश में गयी, आप लोग शिकाकाई की ट्रेनिंग देते हैं, अभी शिकाकाई का दाम उस सरकार ने गिरा दिया है। अभी तेंदू पत्ता की बात कीजिए जो भी अभी minor forest produce है, ट्रेनिंग के बाद भी जो दाम गिर रहे हैं, उसके लिए मार्केटिंग फैडरेशन का क्या कोई रोल हो सकता है कि वह कम से कम दाम की गारंटी दे, ताकि ट्रेनिंग का फायदा ट्रायबल्स को मिले।

श्री तुषारभाई चौधरी : चेयरमैन सर, मैं माननीय सदस्या के विचार से सहमत हूं क्योकि कई बार ऐसा होता है कि जो minor forest gather हैं, उनकी आय इतनी कम हो जाती है कि वह मजबूरन वे काम छोड़कर राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में, जहां पर उनको एक दिन में सौ रुपए मिलते हैं, काम करने चला जाता है। हमारी जानकारी में यह सब आया है इसीलिए हमने इस साल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद को शहद, गोंदकतीरा, महुआ फूल और दोना पत्ता की ट्रेनिंग तथा उसकी सर्वे रिपोर्ट का काम सौंपा है, जिसकी लागत बारह लाख दस हजार है। हम भी उस minor forest produce gathers के प्रति चिंतित हैं और हमारा विभाग भी इस काम के लिए कार्यरत है कि उन्हें कैसे ऊंचा उठाया जाए।

DR. (SHRIMATI) KAPILA VATSAYAYAN : Sir, I wish to ask who are these trainers. In this country. There is a long, long tradition of specialization of these forest gatherers of honey and dona-pattas. Who are the people who are going to train these people, and, what are their qualifications. Secondly, if they have been trained, and, if they have these skills, what is the relevance of these trained people of tribal India with our schemes of education, and, why can't they be put in the primary education as teachers.

श्री तुषारभाई चौधरी : चेयरमैन सर, जहां तक दोना पत्ता का सवाल है, हमने अभी इसके लिए बारह हजार चालीस लोगों को यह ट्रेनिंग दी है। हमने उनको मोल्डिंग मशीन और स्टिचिंग मशीन भी दी है और ज्यादा से ज्यादा जो संगठन है, हम उनको भी ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी : महोदय, सवाल कुछ पूछा जा रहा है और जवाब कुछ दिया जा रहा है।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN : Silence please.

श्री शिवानन्द तिवारी : महोदय, यह क्या तरीका है? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN : Please allow the answer to be completed...*(Interruptions)*.. आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Please allow the answer to be completed.

श्री कमाल अख्तर : इनको ट्रेनिंग दिलवाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : कमाल अख्तर साहब, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़. आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI PENUMALLI MADHU : Mr. Chairman, Sir, the Minister should answer the question...*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN : Mr. Madhu, ...*(Interruptions)*...

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI : Why are you...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN : Please complete the answer...*(Interruptions)*... Please complete the answer.

श्री तुषारभाई चौधरी : चेयरमैन सर, हमने CCI पुणें को भी उसके लिए संकलित किया है और जहां तक minor forest produce gatherers का सवाल है, जैसे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में minor forest produce gatherers फैडेरेशन गवर्नमेंट संस्था है, जो ट्रेनिंग का काम करती है तथा एक NGO भी है, वह ट्रेनिंग का काम करती है। जहां-जहां पर भी हमारा ट्राइबल सबप्लान चल रहा है, उसके अंतर्गत NGO को चुनकर, हम ट्रेनिंग का काम भी कर रहे हैं।

Coal Production

*326. SHRI AMIR ALAM KHAN: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the details of coal production during the last two years, till date, State-wise and company-wise;

(b) whether there is any proposal to close down the underground mines which are unproductive and not viable;

(c) if so, the details thereof, company-wise; and

(d) the steps taken by Government for production and supply of the requisite quantum of coal in the event of closure of these mines?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL) : (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.